

निखिल कंचनला लवखारिया

बनाम

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड व अन्य

(2006 की सिविल अपील संख्या 4210)

15 मई 2008

[तरुण चटर्जी और दलवीर भंडारी, जे जे]

सेबी (स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) नियम, 1992:

विनियमन 10, अनुसूची III, पैरा 4- "शुल्क निरंतरता लाभ" - स्टॉक एक्सचेंज के एक सदस्य का बेटा यह कहते हुए लाभ का दावा करता है कि उसके पिता द्वारा साझेदारी फर्म में नामांकित होने पर, साझेदारी फर्म के सदस्य के रूप में वह हकदार था "शुल्क निरंतरता लाभ" -माना गया: दावेदार के पिता, न कि फर्म स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे और, इस तरह, दावेदार लाभ का हकदार नहीं होगा- सेबी (स्टॉक-ब्रोकरऔरसब-ब्रोकर) नियम, 1992-आरआर 4 और 10-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992-धारा 152।

अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसके पिता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के नाम पर स्टॉक-ब्रोकर का व्यवसाय कर रहे थे; उनके पिता ने, उनके खराब स्वास्थ्य के कारण, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य के रूप में अपने स्थान पर नामांकित किया, और इस प्रकार, वह फर्म के भागीदार बन गए; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को फर्म को शुल्क निरंतरता का लाभ देना चाहिए, क्योंकि पहले पांच वर्षों के लिए बोर्ड पहले ही टर्न-ओवर के आधार पर साझेदारी से शुल्क ले चुका था। इसलिए, इसके बाद फर्म से पंजीकरण के लिए प्रतिवर्ष 5000/- रुपये की

समान दर से शुल्क लिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता का मामला यह था कि ट्रांसमिशन के कारण चूंकि व्यवसाय और व्यापार एक ही नाम या इकाई में जारी रहा और स्टॉक एक्सचेंज ने एक ही नंबर और क्लियरिंग कोड के तहत एक ही सदस्यता जारी रखने की अनुमति दी, इसलिए उन्हें एक ही पंजीकरण के तहत लाभ दिया जाना चाहिए व पहले वाले स्टॉक ब्रोकर की फीस निरंतरता का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। अपीलकर्ता का दावा खारिज कर दिया गया। तात्कालिक अपील सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15Z के तहत दायर की गई थी। अन्य अपील भी इसी तरह की स्थिति में दायर की गई थीं।

सेबी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अपील का विरोध किया कि सेबी अधिनियम, नियमों और/या सेबी के विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो शुल्क देने के उद्देश्य से विरासत और/या ट्रांसमिशन द्वारा स्टॉक ब्रोकरों के पंजीकरण को मान्यता देता हो। निरंतरता लाभ अपीलकर्ता, जो स्टॉक ब्रोकर का बेटा था, ट्रांसमिशन पर, केवल अधिनियम, विनियमों और नियमों के अनुसार सेबी के साथ एक नए स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकृत हो सकता था, और एक नए स्टॉक के लिए पंजीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन था - ब्रोकर के अनुसार विनियमों में निर्धारित अनुसूची; और ऐसे प्रसारण के मामले में शुल्क निरंतरता लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं था।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. वर्तमान मामले में, माना जाता है कि अपीलकर्ता के पिता स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे, न कि फर्म के। आमतौर पर, यदि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की सदस्य नहीं है, तो वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों से निपटने की हकदार नहीं होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साझेदारी फर्मों के सदस्यों का नामांकन नहीं

करता है। इस प्रकार, अकेले अपीलकर्ता के पिता स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे, और वह अकेले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में सौदा करने के हकदार थे। [पैरा 14] [953-डी,ई और एफ]

1.2 विनियमों की स्पष्ट व्याख्या से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजीकरण के उत्तराधिकार का कोई प्रावधान स्वीकार्य नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए दिवंगत सदस्य के बेटे को सेबी से नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा, और पहले पांच वर्षों के लिए उसे टर्न-ओवर से जुड़ी शुल्क की मात्रा का भुगतान करना होगा और उसके बाद फ्लैट दर पर भुगतान करना होगा। रुपये का पंजीकरण को चालू रखने के लिए 5000/- रु. [पैरा 18][955-डी और ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 4210

2004 की अपील संख्या 221 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के दिनांक 12-5-2006 के अंतिम निर्णय और आदेश से

के साथ

2006 की सिविल अपील संख्या 2951, 3004, 3008, 3009, 3010, 3015, 3016, 3017, 3058, 3082

सी.ए. सुंदरम, श्याम दीवान, निशा भक्सी, शशि एम. कपिला, विकास मेहता, बीना गुप्ता, वरुमन खंडेलवाक, एम.के.एस. मेनन, थॉमस जे. अरकापरम्बन और एम.के. मिकासी, अपीलकर्ताओं के लिए।

अल्ताफ अहमद, भार्गव वी.देसाई, राहुल गुप्ता, रीमा शर्मा, राजीव कुमार, जॉयती मेंदीरता और अम्भोज कुमार सिन्हा, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय

दलवीर भंडारी, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलों के इस बैच में समान मुद्दा शामिल है, इसलिए इन सभी अपीलों का निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जाता है। सुविधा के लिए, 2006 की सिविल अपील संख्या 4210 के तथ्यों को दोबारा दोहराया गया है।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 15Z के तहत यह वैधानिक अपील प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई द्वारा 2004 की अपील संख्या 221 में 12 मई, 2006 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

3. आक्षेपित आदेश एक पंक्ति का आदेश है जो 12 मई, 2006 को एक साथी मामले में पारित विस्तृत आदेश का संदर्भ देता है, जिसका शीर्षक 2004 की अपील संख्या 211 है, जिसका शीर्षक कमलेश रमनलाल शाह बनाम सेबी और अन्य है।

4. वह प्रश्न जो "शुल्क निरंतरता लाभ" के संबंध में इस मामले में निर्णय की मांग करता है। सेबी (स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) विनियम, 1992 (संक्षेप में "विनियम") के तहत स्टॉक ब्रोकरों को शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। मोटे तौर पर, शुल्क को दो अलग-अलग चरणों में संरचित किया गया था। किसी ब्रोकर के संचालन के पहले पांच वर्षों में, शुल्क की मात्रा स्टॉक ब्रोकर के टर्नओवर से जुड़ी होती थी। जितना अधिक टर्न-ओवर, उतना अधिक शुल्क।

5. दूसरे चरण में प्रारंभिक पंजीकरण के अनुदान के बाद छठे वित्तीय वर्ष से पांच साल के ब्लॉक शामिल थे। पांच साल की प्रत्येक ब्लॉक अवधि के दौरान, पंजीकरण को लागू रखने के लिए स्टॉक ब्रोकर को रु. 5000/- की एक निश्चित दर का भुगतान करना आवश्यक था। फ्लैट शुल्क का टर्नओवर से कोई संबंध नहीं था।

6. अपीलकर्ता का दावा है कि जब भी ट्रांसमिशन की घटना पांच साल के भीतर होती है, तो उन्हें शुल्क निरंतरता लाभ दिया जाना चाहिए और पांच साल की प्रारंभिक अवधि के शेष के लिए टर्नओवर आधार शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता दावा कर रहा है कि ट्रांसमिशन के कारण, चूंकि व्यवसाय और व्यापार एक ही नाम या इकाई में जारी रहता है और स्टॉक एक्सचेंज एक ही नंबर और क्लियरिंग कोड के तहत एक ही सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, इसलिए उन्हें भी उसी पंजीकरण के तहत लाभ दिया जाना चाहिए। पहले के स्टॉक ब्रोकर का और इस प्रकार शुल्क निरंतरता का लाभ प्रदान करें।

7. अपीलकर्ता के अनुसार, वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति शामिल है जहां हर समय स्टॉक ब्रोकिंग फर्म मेसर्स के नाम और शैली में कारोबार करने वाली एक साझेदारी फर्म थी। कंचनलाल एंड संस. अपीलकर्ता ने अपने बेटे, पत्नी और बहू के साथ मिलकर एक साझेदारी फर्म का गठन किया। स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अपीलकर्ता को उनके स्थान पर स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (प्रतिवादी संख्या 2) के सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह मेसर्स का भागीदार है। कंचनलाल एंड संस और इसलिए, अब भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड (संक्षेप में सेबी) को शुल्क निरंतरता का लाभ देना चाहिए क्योंकि पहले पांच वर्षों के लिए उनसे पहले ही टर्नओवर के आधार पर साझेदारी से शुल्क लिया जा चुका है, इसलिए, उन्हें अब शुल्क लेना होगा पंजीकरण के लिए रु. 5000/- प्रति वर्ष की एक निश्चित दर पर। अपीलकर्ता ट्रांसमिशन के कारण दावा करता है क्योंकि व्यवसाय और व्यापार एक ही नाम या इकाई में जारी रहा और स्टॉक एक्सचेंज एक ही नंबर और क्लियरिंग कोड के तहत एक ही सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है। उन्हें भी पहले के स्टॉक ब्रोकर के समान पंजीकरण और लाभ शुल्क निरंतरता के तहत लाभ दिया जाना चाहिए।

8. सेबी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अल्ताफ अहमद ने कहा कि सेबी अधिनियम, नियमों और/या सेबी के विनियमों में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है जो विरासत और/या ट्रांसमिशन द्वारा स्टॉक ब्रोकरों के पंजीकरण को मान्यता देता हो। शुल्क निरंतरता लाभ देने के उद्देश्य से। अपीलकर्ता, जो ट्रांसमिशन पर स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया का पुत्र है, केवल अधिनियम विनियमों और सेबी (स्टॉक-ब्रोकर और सब-ब्रोकर) नियम, 1992 (संक्षेप में “द) के अनुसार सेबी के साथ एक नए स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकृत हो सकता है। नियम”) और विनियमों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नए स्टॉक-ब्रोकर के लिए पंजीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे ट्रांसमिशन के मामलों में शुल्क निरंतरता लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। एकमात्र स्थिति जिसके अंतर्गत शुल्क निरंतरता लाभ प्रदान किया जाता है विनियमों के विनियम 10 के तहत अनुसूची III के पैरा 4 के तहत, जो इस प्रकार है:

“4. जहां एक्सचेंज के व्यक्तिगत या साझेदारी सदस्यता कार्ड को परिवर्तित करके एक कॉर्पोरेट इकाई का गठन किया गया है, ऐसी कॉर्पोरेट इकाई को उस अवधि के लिए शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी जिसके लिए पूर्ववर्ती व्यक्तिगत या साझेदारी सदस्य, जैसा भी मामला हो, इस शर्त के अधीन पहले ही शुल्क का भुगतान कर दिया है कि पूर्ववर्ती व्यक्ति या भागीदार इस प्रकार परिवर्तित कॉर्पोरेट सदस्य का पूर्णकालिक निदेशक होगा और ऐसे निदेशक के पास कॉर्पोरेट इकाई की चुकता इक्विटी पूंजी के न्यूनतम 40% शेयर बने रहेंगे। ऐसे रूपांतरण की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि।

स्पष्टीकरण-यह स्पष्ट किया जाता है कि एक्सचेंज के व्यक्तिगत या साझेदारी सदस्यता कार्ड का कॉर्पोरेट इकाई में रूपांतरण पुरानी इकाई की निरंतरता में माना

जाएगा और उस अवधि के लिए परिवर्तित कॉर्पोरेट इकाई से कोई शुल्क दोबारा नहीं लिया जाएगा। संस्था ने नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान कर दिया है।“

9. श्री अहमद ने आगे तर्क दिया कि यह निगमीकरण के लिए एक प्रोत्साहन था क्योंकि एक कॉर्पोरेट इकाई को कानून के तहत सभी रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है और इस तरह यह स्टॉक ब्रोकरों को विनियमित करने की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी अन्य परिस्थिति में वैधानिक नियमों के तहत शुल्क निरंतरता का लाभ उपलब्ध नहीं है और इसलिए अपीलकर्ता को ट्रांसमिशन के कारण शुल्क निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

10. श्री अहमद ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्येक स्टॉक-ब्रोकर जो प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों का सौदा करना चाहता है, उसे स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होना आवश्यक है और फिर प्रक्रिया के अनुसार अधिनियम की धारा 12 के तहत सेबी के साथ खुद को पंजीकृत कराना होगा। जैसा कि विनियमन में प्रदान किया गया है, अनुसूची-III में उल्लिखित दरों पर नियमों के नियम 4 और विनियम 10 के तहत एक नए स्टॉक-ब्रोकर के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

नियमों का नियम 4 इस प्रकार है:

”4. स्टॉक-ब्रोकर को प्रमाणपत्र प्रदान करने की शर्तें.-द बोर्ड किसी स्टॉक-ब्रोकर को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है:-

- 1) उसके पास किसी स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता है;
- 2) वह उस स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, विनियमों और उपनियमों का पालन करेगा, जिसका वह सदस्य है

3) स्थिति और संविधान में किसी भी बदलाव के मामले में, स्टॉक-ब्रोकर को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन जारी रखने के लिए बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी;

4) वह पंजीकरण के लिए शुल्क की राशि का भुगतान करेगा विनियमों में प्रदान किया गया तरीका; और

5) वह शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा और बोर्ड को ऐसे निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, प्रकृति और अन्य विशिष्टताओं के बारे में सूचित रखेगा।

विनियमों का विनियम 10 इस प्रकार है:

"10. फीस का भुगतान और फीस का भुगतान करने में विफलता के परिणाम।

(1) प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक को ऐसी फीस और अनुसूची III में निर्दिष्ट तरीके से भुगतान करना होगा; बशर्ते कि बोर्ड पर्याप्त कारण बताए जाने पर स्टॉक-ब्रोकर को ऐसी फीस देय होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले किसी भी समय ऐसी फीस का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है।

(2) जहां एक स्टॉक-ब्रोकर विनियमन 10 में प्रदान की गई फीस का भुगतान करने में विफल रहता है, बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकता है, जिसके बाद स्टॉक-ब्रोकर स्टॉक-ब्रोकर के रूप में प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या सौदा करना बंद कर देगा।"

11. श्री अहमद ने तर्क दिया कि स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनने के लिए, व्यक्ति को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 8 के अनुसार योग्य होना आवश्यक है। यह अधिकार भी विरासत में नहीं मिला है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ट्रांसमिशन पर किसी विशेष स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनने के लिए भी योग्य नहीं हो

सकता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता एक विशेषाधिकार है न कि अधिकार का मामला और इस प्रकार इसे विरासत के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

12. श्री अहमद ने यह भी तर्क दिया कि सेबी के पास अधिनियम, नियमों या विनियमों के कार्यान्वयन में कोई विवेकाधिकार नहीं है और उसे निर्धारित प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा और इसलिए उसके पास उक्त आवश्यकता को छोड़ने की कोई शक्ति नहीं है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक हो सकता है कि 19 स्टॉक ब्रोकरों में से जिन्होंने ट्रांसमिशन पर नए पंजीकरण या नई संस्थाओं की छूट के लिए प्रार्थना की थी, केवल 9 या 10 ही इस अदालत के समक्ष चुनौती देने आए हैं और शेष ने विद्वान के फैसले को स्वीकार कर लिया है।

13. श्री अहमद ने आगे कहा कि सेबी ने 1992-93 से 1996-97 की अवधि के लिए टर्नओवर व्यवस्था लागू की है और इसलिए, फ्लैट दर के आधार पर शुल्क लिया गया है। विनियमों की अनुसूची III का खंड (1)(सी) इस प्रकार है:

“स्टॉक-ब्रोकर के रूप में प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से पांच वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद, वह प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख के बाद छठे वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वित्तीय वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के लिए पांच हजार रुपये का भुगतान करेगा। उसके पंजीकरण को लागू रखने के लिए।”

14. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि, अधिनियम की धारा 12 के तहत, कोई भी व्यक्ति सेबी के साथ पंजीकृत हुए बिना प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों का सौदा नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि अपीलकर्ता के पिता स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे, न कि फर्म मैसर्स। कंचनलाल एंड संस. सामान्यतः, यदि मै. कंचनलाल एंड संस स्टॉक

एक्सचेंज का सदस्य नहीं है, कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों से निपटने की हकदार नहीं होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साझेदारी फर्म को सदस्यों के रूप में नामांकित नहीं करता है। इस प्रकार, स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया अकेले स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे और वे अकेले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में सौदा करने के हकदार थे। हालाँकि, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नियम 179 के तहत, एक व्यक्तिगत सदस्य कुछ वर्गीकृत संबंधों के साथ साझेदारी में व्यापार कर सकता है और इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म के नाम पर व्यापार करने की अनुमति देता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नियम 179 इस प्रकार है:

“179. कोई भी साझेदारी तब तक नहीं बनाई जाएगी जब तक-

- i. दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अदला-बदली; या
- ii. एक्सचेंज के एक सदस्य और उसके पिता या मां या पत्नी या उसके बेटे या बेटों या बेटी या बहू या पिता के भाई या भाइयों या अविवाहित बहन या बहनों या परेशान या भाई के बेटे या बेटों के बीच; या
- iii . एक्सचेंज के दो या दो से अधिक सदस्यों और उनके पिता, माता या पत्नियों या बेटे या बेटों या बेटी या बेटियों या बहू या बहुओं या भाई या भाइयों या पिता के भाई या भाइयों या अविवाहित बहन या बहनों के बीच या भाई या भाई के बेटे या

बशर्ते कि किसी बेटे या बेटी या बेटे के बेटे या भाई या पिता के भाई या भाई की अविवाहित बहन को साझेदारी में नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह सभी तरह से एक्सचेंज की सदस्यता के लिए पात्र न हो।

15. श्री अहमद ने इस बात पर संतोष जताया कि स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया अकेले सदस्य थे और उनकी साझेदारी के माध्यम से, पूरी साझेदारी फर्म को

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार का पूरा कारोबार है व्यक्तिगत सदस्य स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया से संबंधित, अन्यथा साझेदारी फर्म और गैर-सदस्य भागीदार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का सौदा करने में सक्षम नहीं होते। नतीजतन, यह साझेदारी फर्म तब तक प्रतिभूतियों का सौदा नहीं कर सकती जब तक कि स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य अर्थात् व्यक्तिगत सदस्य स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया सेबी के साथ पंजीकृत न हो जाए। उस व्यक्तिगत सदस्य स्वर्गीय श्री के. वखारिया के माध्यम से ही साझेदारी फर्म और पंजीकृत भागीदार बनते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में सौदा करने में सक्षम हैं। अन्यथा भी स्टॉक एक्सचेंज पर साझेदारी फर्म का पूरा कारोबार प्रतिभूतियों पर होता है और इसलिए यह पंजीकृत सदस्य यानी स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया से संबंधित है, जिनकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता और सेबी के पंजीकरण के तहत इस तरह के व्यापार की अनुमति है।

16. सेबी की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता केवल अपने टर्नओवर को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में माना जाना चाहता है और अन्य भागीदार गैर-सदस्य भागीदार होने के कारण सेबी के पंजीकरण के दायरे से बाहर रहना चाहते हैं क्योंकि वे पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया की सदस्यता और पंजीकरण के तहत एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों का सौदा करना चाहता हूँ।

17. सेबी के विद्वान वकील के अनुसार, गैर-सदस्य भागीदारों द्वारा प्रतिभूतियों में संपूर्ण लेनदेन अवैध होगा और अधिनियम की धारा 12 के विपरीत होगा और कानून में ऐसे सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। वास्तव में यदि लिया गया रुख सही है तो साझेदारी फर्म भी गैर-सदस्य साझेदारी है और प्रतिभूतियों में सौदा नहीं कर सकती है, लेकिन कानून का उल्लंघन करते हुए प्रतिभूतियों में कारोबार कर रही है।

18. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है। विनियमों की स्पष्ट व्याख्या से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजीकरण के उत्तराधिकार का कोई प्रावधान स्वीकार्य नहीं है। स्वर्गीय श्री कंचनलाल के. वखारिया के पुत्र निखिल के. वखारिया को स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए सेबी से नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा और पहले पांच टर्नओवर के लिए और उसके बाद 5000/- रुपये की फ्लैट दर पर भुगतान करना होगा। पंजीकरण को लागू रखने के लिए।

19. अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के मद्देनजर हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है कि अपील में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

2006 की सिविल अपील संख्या 2951, 3004, 3008, 3009, 3010, 3015, 3016, 3017, 3058, 3082:

20. 2006 की सिविल अपील संख्या 4210 में हमारे फैसले के मद्देनजर इन अपीलों का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम सभी अपीलों के पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश देते हैं।

आर.पी.

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नवीन सिंह गुर्जर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।